All-Inclusive Current Affairs for Prelims 2023

Economy Class-17

पेटेंट अभियोजन राजमार्ग *Patent Prosecution Highway*

❖ **पेटेंट लिटिगेशन** : पेटेंट के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
❖ **पेटेंट प्रॉसिक्यूशन** : पेटेंट के लिए आवेदन करना

द्विपक्षीय PPH :
- दो देशों के पेटेंट कार्यालयों के बीच जानकारियों का आदान-प्रदान
- 2019 में भारत-जापान ने **PPH** समझौते पर हस्ताक्षर किए

वैश्विक PPH :
- कई देशों के पेटेंट कार्यालयों के बीच जानकारियों का आदान-प्रदान
- यह **WIPO** की पहल है । भारत इसमें हिस्सा 'नहीं' ले रहा है।

पेटेंट अभियोजन राजमार्ग
- पेटेंट आवेदन के फास्ट ट्रैक परीक्षण के लिए
- पेटेंट कार्यालय किसी पेटेंट आवेदन से सम्बंधित अपने निष्कर्ष आपस में साझा करते हैं

IPR

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक
- **US** चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा

L2Pro (अपने नवोत्पादों को संरक्षित, सुरक्षित रखना सीखें और बढ़ाएं)
- CIPAM (DPIIT (MoCI) के तहत) द्वारा
- IPR सुरक्षा के बारे में जानकारी हेतु जनता के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म

CIPAM
- DPIIT (MoCI) के तहत आता है
- IPR संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion And Management)
- राष्ट्रीय **IPR नीति 2016** को लागू करने के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)
- छात्रों में बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करना
- ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स द्वारा

राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति
- 2019 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया
- उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों के लिए

- ❑ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) (MoC&I) मुंबई में है।
- ❑ पेटेंट कार्यालय **कोलकाता** में है
- ❑ डिजाइन कार्यालय **कोलकाता** में है
- ❑ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री **मुंबई** में है
- ❑ GI रजिस्ट्री **चेन्नई** में है
- ❑ कॉपीराइट रजिस्ट्री **दिल्ली** में है

2016 में NITI Aayog द्वारा **अटल इनोवेशन मिशन** लॉन्च किया गया।

अटल टिंकरिंग लैब्स	स्कूल्स में
अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स	विश्वविद्यालयों और कंपनियों में
अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र	टीयर-2/3 शहरों, आकांक्षी जिलों, आदिवासी, पहाड़ी, तटीय क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में
अटल न्यू इंडिया चैलेंज	सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले नवाचारों के लिए
ARISE-ANIC	स्टार्टअप/MSME के लिए
मेंटर ऑफ़ चेंज (Mentor of Change)	सलाहकारों को शामिल करना जो दूसरों की मदद कर सकते हैं

भारत नवाचार सूचकांक
- **नीति आयोग** द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशन
- 2019 में शुरू हुआ

श्रेणियाँ	पहला	अंतिम
प्रमुख राज्य	कर्नाटक	छत्तीसगढ
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य	मणिपुर	नगालैंड
UT और सिटी स्टेट्स	चंडीगढ़	लद्दाख

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
- **WIPO** द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशन
- INSEAD द्वारा 2007 में शुरू किया गया

#01 विश्व में	स्विट्ज़रलैंड
#40 विश्व में	भारत
#01 मध्य और दक्षिण एशिया में	भारत
#01 निम्न मध्यम आय वर्ग में	भारत

डिजिटल इनोवेशन एलायंस	स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान
मानवता की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स द्वारा विकसित डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना	सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान आदि पर सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना
Meity द्वारा लॉन्च किया गया (भारत के G20 Presidency के तौर पर)	

ALL INCLUSIVE IAS

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- 1967; जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- IPR को प्रोत्साहित करने और संरक्षण देने हेतु
- संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी
- 193 सदस्य (भारत? हाँ)

WIPO द्वारा 26 संधिया प्रशासित की जाती है। उनमें से कुछ :

1957	नाइस एग्रीमेंट	ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क्स
1968	लोकार्नो एग्रीमेंट	औद्योगिक डिजाइन
1971	स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट	पेटेंट
1973	वियना एग्रीमेंट	आलंकारिक (Figurative) तत्व

2018 में भारत ने मंजूरी दी:-

- ✓ WIPO कॉपीराइट संधि
- ✓ WIPO परफॉर्मन्सेस एंड फोनोग्राम्स संधि

मिशन इनोवेशन

- स्वच्छ ऊर्जा में नवाचारों के लिए एक वैश्विक पहल
- CoP-21 (2015, पेरिस) में 20 देशों (भारत, चीन, USA, UK आदि) द्वारा लॉन्च किया गया था।

Prelims 2018

भारत ने माल के भौगोलिक संकेत (रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया?

(a) ILO (b) IMF (c) UNCTAD **(d) WTO**

Prelims 2010

ट्रिप्स (TRIPS) समझौते का पालन करने के लिए, भारत ने माल के भौगोलिक संकेत (रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया। "व्यापार चिन्ह" (ट्रेडमार्क) और "भौगोलिक संकेत" (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन) के बीच निम्नलिखित अंतर है / हैं:

1. व्यापार चिन्ह एक व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार है जबकि भौगोलिक संकेत एक समुदाय का अधिकार है ।
2. व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है जबकि भौगोलिक संकेतक को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है ।
3. व्यापार चिन्ह उत्पादित माल के लिए समनुदेशित किया जाता है जबकि भौगोलिक संकेत केवल कृषि माल/उत्पाद तथा हस्तशिल्प के लिए समनुदेशित किया जाता है ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) 1 और 2** (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Prelims 2017

'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स (TRIPS) समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है ।
2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPR) के विनियमन के लिए केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 **(c) 1 और 2 दोनों** (d) न तो 1 और न ही 2

Prelims 2019

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। ***गलत***
2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। ***2023 में सही, 2019 में गलत***
3. पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। ***सही***

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

2019 में उत्तर: (c) **2023 में उत्तर: (b)**

नोट

- 2019 में, SC ने फैसला सुनाया कि मोनसेंटो की बोलगार्ड-II बीटी कॉटन सीड टेक्नोलॉजी (एक GM वैरिएंट, जो बॉलवर्म कीट का प्रतिरोध/मुकाबला करता है) का पेटेंट भारत में लागू है।
- ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 ने **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड** (IPAB) सहित विभिन्न न्यायाधिकरणों (tribunals) को समाप्त कर दिया और उनके कार्यों को वाणिज्यिक न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को सौंप दिया।

पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार, निम्नलिखित में से किसका पेटेंट कराया जा सकता है?

म्यूजिक? नहीं
उपन्यास? नहीं
कंप्यूटर प्रोग्राम? नहीं
कृषि के तरीके? नहीं
एक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज? नहीं
बीज, पौधे, जानवर? नहीं
सूक्ष्म जीव? हाँ

कुछ IPR संबंधित कानून

- ❑ कॉपीराइट अधिनियम, 1957
- ❑ पेटेंट अधिनियम, 1970
- ❑ भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999
- ❑ ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999
- ❑ डिजाइन अधिनियम, 2000
- ❑ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम, 2000
- ❑ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
- ❑ जैविक विविधता अधिनियम, 2002

MPEDA/APEDA

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
MPEDA अधिनियम, 1972 के तहत एक वैधानिक निकाय	APEDA अधिनियम, 1985 के तहत एक वैधानिक निकाय
वाणिज्य विभाग, MoC&I के अंतर्गत स्वायत्त निकाय	वाणिज्य विभाग, MoC&I के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
यह निर्यातकों को प्रमाणपत्र देता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।	यह निर्यातकों को प्रमाणपत्र देता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।
SHAPHARI प्रमाणन योजना :- एंटीबायोटिक मुक्त झींगा बीजों के उत्पादन के लिए हैचरी (अंडे सेने की जगह) हेतु	NPOP के तहत आर्गेनिक निर्यात के लिए प्रमाणन निकायों को मान्यता देने हेतु नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड (NAB) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (NaCSA) द्वारा e-Santa लॉन्च किया गया है	सरकार ने APEDA को चीनी के आयात पर नजर रखने को कहा है

नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर
- यह MPEDA के अंतर्गत आता है
- यह एक्वा किसानों का समर्थन करने के लिए SHG पद्धति का उपयोग करता है
- इसने एक्वा किसानों को निर्यातकों से सीधे जोड़ने के लिए e-Santa लॉन्च किया है

APEDA निम्नलिखित में से किन उत्पादों को बढ़ावा देता है?
- ✓ फल, सब्जियां, अनाज
- ✓ बिस्कुट, चॉकलेट
- ✓ औषधीय पौधे
- ✓ बासमती चावल
- ✓ डेयरी, पोल्ट्री, मांस
- ✓ ग्वार गम
- ✓ मादक पेय
- ✓ फूल

और भी बहुत कुछ...

APEDA (संशोधन) अधिनियम, 2009 https://apeda.gov.in/apedawebsite/about_apeda/bas_ex_dev_found.htm
- ❑ इसने APEDA को भारत के विशेष उत्पादों के IPR के पंजीकरण और संरक्षण का अधिकार दिया
- ❑ APEDA अधिनियम में 2nd Schedule जोड़ा गया जिसमे ऐसे विशेष उत्पादों के नाम होंगे
- ❑ वर्तमान में, 2nd Schedule में **केवल एक प्रविष्टि** ("बासमती चावल") है

2016 में, APEDA को बासमती चावल के लिए GI Tag का पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला (GI रजिस्ट्री,चेन्नई द्वारा)
बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन APEDA के तहत काम करने वाली एक सोसायटी है

कृषि जनगणना
Agriculture census

पहली कृषि जनगणना : 1970-71
11वीं कृषि जनगणना : 2021-22 अगस्त 2022 में शुरू हुई

विश्व कृषि गणना
FAO द्वारा
1930, 1950, तब से हर 10 साल बाद
विभिन्न देशों की जनगणना से डेटा लेता है

कृषि जनगणना
- MoA&FW द्वारा राज्यों / UT के सहयोग से
- ऑपरेशनल होल्डिंग को एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में लिया जाता है
- यह हर 5 साल बाद किया जाता है
- इसे तीन चरणों में किया जाता है

ऑपरेशनल होल्डिंग का औसत आकार
- ❑ 2015-16 : 1.08 हेक्टेयर
- ❑ 1970-71 : 2.28 हेक्टेयर

Number of operational holdings as per different Agriculture Censuses

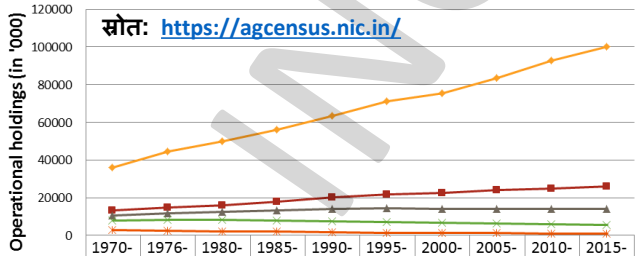

स्रोत: https://agcensus.nic.in/

	1970-71	1976-77	1980-81	1985-86	1990-91	1995-96	2000-01	2005-06	2010-11	2015-16	
Marginal	36200	44523	50122	56147	63389	71179	75408	83694	92826	100251	लगातार वृद्धि हुई
Small	13432	14728	16072	17922	20092	21643	22695	23930	24779	25809	लगातार वृद्धि हुई
Semi-Medium	10681	11666	12455	13252	13923	14261	14021	14127	13896	13993	
Medium	7932	8212	8068	7916	7580	7092	6577	6375	5875	5561	
Large	2766	2440	2166	1918	1654	1404	1230	1096	973	838	लगातार कमी हुई

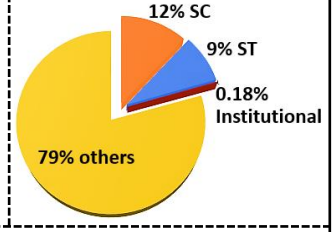

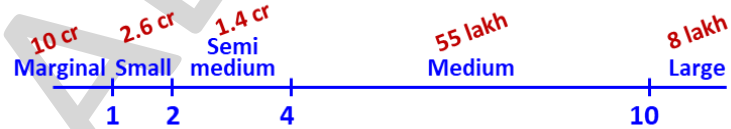

कृषि जनगणना के पैरामीटर
ऑपरेशनल होल्डिंग्स की संख्या और क्षेत्र, उनका आकार, वर्ग-वार वितरण, भूमि उपयोग, काश्तकारी, फसल पैटर्न आदि

ALL INCLUSIVE IAS

डिजिटल कृषि Digital Agriculture

डिजिटल कृषि / ई-कृषि / स्मार्ट खेती

- खाद्य प्रणालियों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग
- जैसे परिशुद्ध खेती (Precision Agriculture), कृषि मशीनरी रेंटल ऐप, वेयरहाउस रिसीप्ट सिस्टम, ब्लॉकचेन- आधारित फूड ट्रैसेबिलिटी सिस्टम, ई-कॉमर्स इत्यादि ।

परिशुद्ध खेती (Precision Agriculture)

- ❑ यह साइट-आधारित फसल प्रबंधन तकनीक है
- ❑ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सटीक मात्रा में इनपुट का उपयोग ।
- ❑ विभिन्न प्रकार के सेंसर, GPS, रिमोट सेंसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, स्प्रेयर, स्वचालित फार्म मशीन (ट्रैक्टर, कंबाइन आदि) का प्रयोग ।

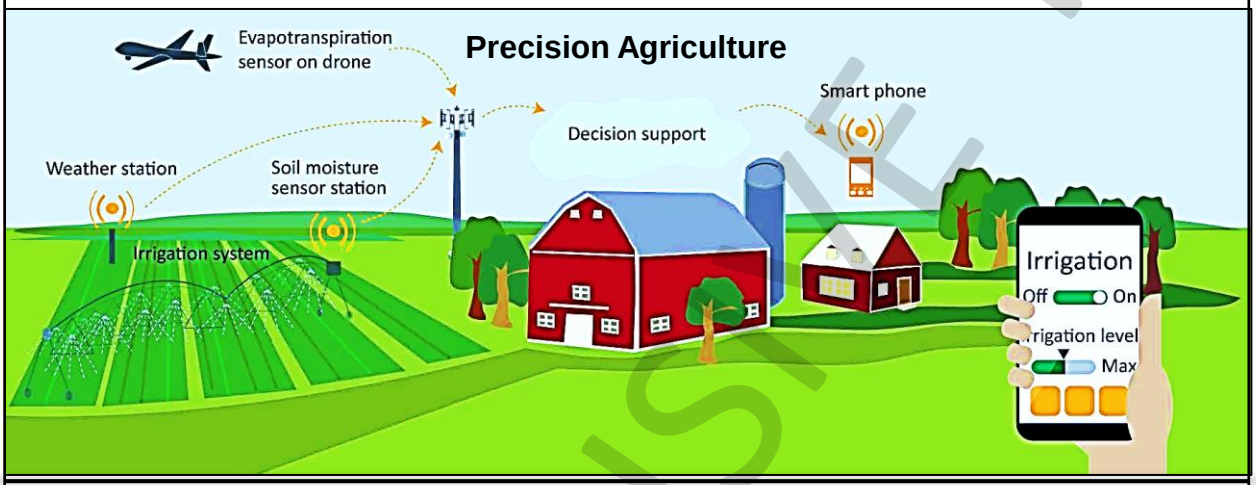

एग्रीस्टैक Agristack

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Government is in the process of finalising 'India Digital Ecosystem of Agriculture (IDEA)' which will lay down a framework for Agristack

Posted On: 03 AUG 2021 6:46PM by PIB Delhi

कृषि में प्रौद्योगिकी और डिजिटल डेटाबेस का संग्रह

अवयव Components

- फार्मर स्टैक : आधार (विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में) के साथ किसानो का डेटा
- फार्म स्टैक : प्रत्येक खेत की भू-स्थानिक (Geo-spatial) जानकारी
- क्रॉप स्टैक : खेतों से जुड़ा क्रॉप डेटा
- भूमि रिकॉर्ड , सरकारी योजनाएं जैसे SHC, PM-FBY, PM-Kisan आदि।

अनाथ फसलें Orphan crops

उपेक्षित और कम उपयोग वाली फसलें

स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं

फसल प्रजनकों और शोधकर्ताओं की इनमें रुचि नहीं है

कृषि विस्तार Agri extension

किसान शिक्षा के जरिए वैज्ञानिक शोध और ज्ञान का कृषि पद्धतियों में प्रयोग करना

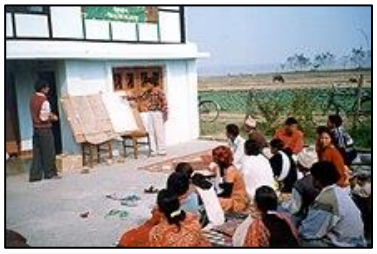

जैविक आधार Organic Aadhaar

आधार + ULPIN

- ❑ APEDA 'ऑर्गेनिक आधार' शुरू करने पर विचार कर रहा है
- ❑ यह NPOP के तहत जैविक खेती करने वाले किसान और उनकी भूमि की पहचान करने में मदद करेगा
- ❑ यह किसान की पहचान के लिए 12 अंकों की आधार संख्या और भूमि की पहचान के लिए 14 अंकों की 'विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या' (Unique Land Parcel Identification Number) का उपयोग कर सकता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड Soil Health Card

Soil Type: Black soil				
Sr.No.	Parameter	Test Value	Unit	Rating	Normal Level
1	pH	6.59		Acidic	7: Neutral
2	EC	0.37	dS/m	Normal	0 - 2 dS/m
3	Organic Carbon (OC)	0.40	%	Low	0.51 - 0.75%
4	Available Nitrogen (N)	305.00	kg/ha	Medium	280 - 560 kg/ha
5	Available Phosphorus (P)	36.00	kg/ha	High	11-26kg/ha
6	Available Potassium (K)	69.00	kg/ha	Low	120-280kg/ha
7	Available Sulphur (S)	36.00	ppm	Sufficient	> 10 ppm
8	Available Zinc (Zn)	6.20	ppm	Sufficient	> 0.6 ppm
9	Available Boron (B)	2.21	ppm	Sufficient	> 0.5 ppm
10	Available Iron (Fe)	37.40	ppm	Sufficient	> 4.5 ppm
11	Available Manganese (Mn)	20.10	ppm	Sufficient	> 2.0 ppm
12	Available Copper (Cu)	5.90	ppm	Sufficient	> 0.2 ppm

यह किसान को उसकी मिट्टी में पोषक तत्व बताता है और जरुरी पोषक तत्वों की मात्रा की सलाह देता है

वर्ष 2015
मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
मिशन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148602
यह सभी किसानों को हर **2 साल** में जारी किया जाता है
एक फार्म को हर **3 साल** में एक बार मृदा कार्ड मिलेगा

भौतिक पैरामीटर	**pH** मान (हाइड्रोजन की क्षमता), **EC** (विद्युत चालकता), **OC** (आर्गेनिक कार्बन)
स्थूल पोषक तत्व	प्राथमिक: **NPK** (नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम) माध्यमिक: **S** (सल्फर)
सूक्ष्म पोषक तत्व	**Fe** (आयरन), **Cu** (कॉपर), **Mn** (मैंगनीज), **Zn** (जिंक), **Bo** (बोरॉन)

Trick to learn → (**FeCu** tum) (**Mn** ki baat) (**Z**aba**n** se) (**Bo**lo)

प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व

प्राथमिक पोषक तत्व
जैसे नाइट्रोजन (**N**), फास्फोरस (**P**), पोटेशियम (**K**)
पौधों को इनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है

माध्यमिक पोषक तत्व
जैसे कैल्शियम (**Ca**), मैग्नीशियम (**Mg**), सल्फर (**S**)
पौधों को इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है

Prelims 2017 राष्ट्रव्यापी ' **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम)' का उद्देश्य है
1. सिंचित कृषियोग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
2. मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना।
3. कृषि भूमि में उर्वरकों के अति-उपयोग को रोकना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 3** *(c)* केवल 2 और 3 *(d) 1, 2* और 3

फसल बीमा Crop Insurance

1985 : व्यापक फसल बीमा योजना
1999 : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
2016 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

Prelims 2016
'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर दो प्रतिशत की एक समान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा।
2. यह योजना, चक्रवात एवं गैर-मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई-उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 **(b) केवल 2**
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- MoA&FW द्वारा खरीफ 2016 में लॉन्च की गयी थी
- बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के चरण तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा प्रदान करता है।
- अधिसूचित क्षेत्रो में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान (बटाईदारों और काश्तकारों सहित) इस योजना के लिए पात्र हैं ।
- पहले यह योजना कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य थी। लेकिन अब यह वैकल्पिक है ।

जानवरों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है?
राज्य इसे ऐड-ऑन कवर के रूप में प्रदान कर सकते हैं

प्रीमियम
बीमा राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है

बीमा कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम की सीमा:
कोई सीमा नहीं

किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की सीमा

रबी की फसलें	1.5%
खरीफ की फसलें	2%
व्यावसायिक/ बागवानी फसलें	5%

शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से किया जाता है
- **50:50** सामान्यतः
- 90:10 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

योजना के उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देना
- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना
- किसानो की आय में स्थिरता लाना और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करना
- किसानो को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

चावल

बासमती चावल
- एक प्रकार का लम्बे दानेवाला सुगंधित चावल
- भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है
- भारत और पाकिस्तान, यूरोप को बासमती निर्यात करते हैं
- GI tag : **APEDA** को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP में (लेकिन MP नहीं)

केरल की कुछ GI tag चावल की किस्में
पोक्कली , नवर, कैपड , वायनाड जीरकसल , वायनाड गंधकसल , पलक्कडन मट्टा

भारत का चावल का कटोरा Rice bowl of India
कृष्णा-गोदावरी बेसिन

कालानमक चावल
- इसे तराई क्षेत्र में उगता है
- पूर्वी यूपी के 11 जिलों को **GI tag** मिला हुआ है
- छिलका काला और सुगंध तेज होती है
- भगवान बुद्ध ने इसे श्रावस्ती के लोगों को उपहार में दिया था ताकि वे इसकी सुगंध से उन्हें याद रखें
- 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत, यह सिद्धार्थनगर का उत्पाद है

Pic 1 : कालानमक चावल का काला छिलका
Pic 2 : कालानमक चावल के दाने

पोक्कली धान
- चावल की एक किस्म; लवणीय पानी सहन क्षमता
- केरल में चावल की सबसे पुरानी किस्मों में से एक
- पानी से भरे तटीय केरल में उगाया जाता है (GI tag ? हाँ)
- जैविक तरीको से उगाया जाता है (ज्वार और मछली/झींगा के मलमूत्र से पोषक तत्व प्राप्त करता है)
- बारी-बारी से, एक सीजन में चावल की खेती और दूसरे सीजन में मछली/झींगा पालन किया जाता है

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
- स्थापना:-1960
- मुख्यालय:- फिलीपींस

भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Rice Research)
- 1965, हैदराबाद
- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत आता है
- इसे पहले चावल अनुसंधान निदेशालय (DRR) के रूप में जाना जाता था
- DRR Dhan xx (xx कोई भी संख्या) IIRR द्वारा विकसित चावल की किस्म है

निहोंशु (या सके)
- यह जापान में चावल से बनी शराब है
- यह पहली बार है जब जापान ने भारत में **GI tag** के लिए आवेदन किया है

सामान्य चावल रोग
- बैक्टीरियल ब्लाइट:- बैक्टीरिया **Xanthomonas oryzae** के कारण
- राइस ब्लास्ट (पत्ती और कॉलर):- फंगस **Magnaporthe oryzae** के कारण

कर्जमाफी vs राइट-ऑफ

Waiver vs Write-off

ET THE ECONOMIC TIMES

No farm loan waiver scheme by Centre in last 5 years: Minister Bhagwat Karad

Last Updated: Mar 28, 2022, 06:24 PM IST

ET THE ECONOMIC TIMES

Bad loans worth Rs 10 lakh cr written off by banks in last five financial years, says Nirmala Sitharaman

Last Updated: Dec 13, 2022, 09:11 PM IST

कर्जमाफी	लोन राइट-ऑफ
बैंकों द्वारा सरकार के आदेश पर किया जाता है	बैंकों द्वारा बिना सरकारी आदेश के किया जाता है
आमतौर पर छोटे किसानों के लिए किया जाता है	आमतौर पर बड़ी कंपनियों के लिए किया जाता है
बाद में बैंक कर्ज वसूली का प्रयास नहीं करता है	बाद में भी बैंक पैसे वसूलने की कोशिश करता रहता है
बैंक के पास रखा हुआ कोलैटरल (गिरवी वस्तु) उसके मालिक को रिटर्न कर दिया जाता है	बैंक के पास रखा हुआ कोलैटरल जब्त कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है

उत्पादकता Productivity

$$Productivity = \frac{Output}{Input}$$

उत्पादकता से पता चलता है कि संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं में कितनी कुशलता से परिवर्तित किया गया है

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
DPIIT के तहत एक स्वायत्त निकाय (MoC&I)

भारत उत्पादकता रिपोर्ट
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा (RBI के सहयोग के साथ)

समय की गरीबी Time Poverty

समय गरीबी
- काम की अधिकता के कारण स्वयं के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाना
- जैसे महिलाओं को घर से बाहर की गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाना

समय बैंकिंग
- सेवाओं की एक वस्तु विनिमय प्रणाली (barter system), जिसमे लोग बराबर समय के लिए सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं
- जैसे 'A' 'B' के लिए 1 घंटे कुकिंग करती है और 'B' 'A' के पशुओं की 1 घंटे देखभाल करती है

मार्ग (MAARG)

#startupindia
maarg
MENTORSHIP • ADVISORY • ASSISTANCE
RESILIENCE • GROWTH

मार्ग पोर्टल
DPIIT (MoC&I) का ऑनलाइन पोर्टल स्टार्टअप्स और मेंटर्स को जोड़ने के लिए

मिश्रित वित्त Blended Finance

सतत विकास परियोजनाओं के लिए निजी धन को आकर्षित करने के लिए, पब्लिक फंड और दान कोष का उपयोग करना ।

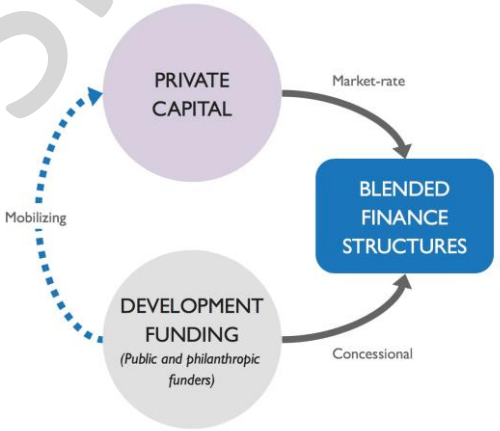

क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग Crypto-Asset Reporting

- OECD द्वारा बनाया गया
- कर चोरी (Tax Evasion) आदि को रोकने में देशों की मदद करेगा
- क्रिप्टो-एसेट के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक

डोनट अर्थव्यवस्था Doughnut Economy

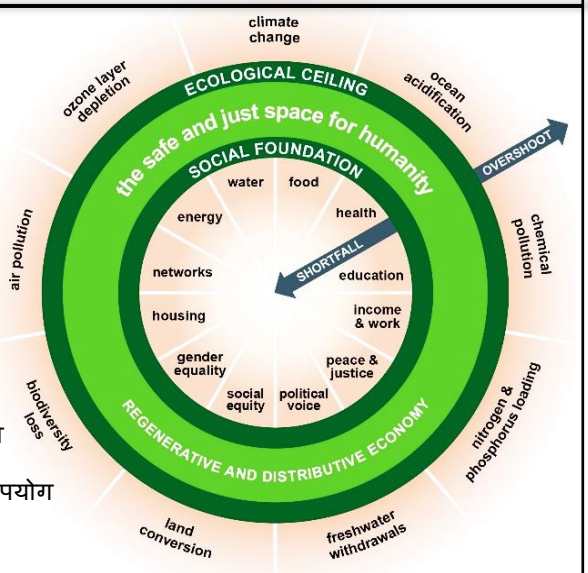

डोनट का केंद्रीय छिद्र
➢ लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं (भोजन, पानी, आदि) की कमी

डोनट
➢ गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए संसाधनों का सतत/संतुलित उपयोग

डोनट के बाहर का क्षेत्र
➢ संसाधनों का असंतुलित दोहन

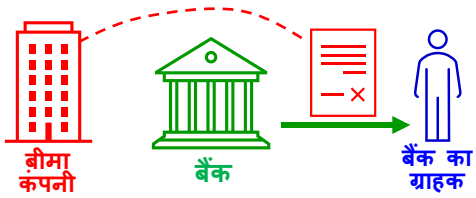

बैंकाश्योरेंस Bancassurance

- यह एक बैंक और बीमा कंपनी के बीच एक समझौता है
- यह बैंक को अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचने की अनुमति प्रदान करता है

BBPS

BHARAT BILLPAY

Operating area	India
Founded	2013; 10 years ago
Owner	NPCI
Website	www.bharatbillpay.com

भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)

- यह एक इंटरऑपरेबल बिल-भुगतान सेवा है
- यह लगभग सभी भुगतान विधियों को स्वीकार करती है
- NPCI द्वारा बनाया गया
- बिल: बिजली, पानी, गैस, दूरसंचार, बीमा, लोन, शिक्षा, फास्टैग आदि

Note

- 2013 में RBI ने भारत में (यूरोप की तरह) गिरो आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
- गिरो ट्रांसफर में, भुगतान भुगतानकर्ता द्वारा शुरू किया जाता है, न कि प्राप्तकर्ता द्वारा।

ONDC

- DPIIT की पहल पर 2021 में बनाया गया
- यह एक गैर-लाभकारी संगठन है (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत)
- संस्थापक सदस्य: भारतीय गुणवत्ता परिषद् (QCI) और Protean eGov Technologies Limited

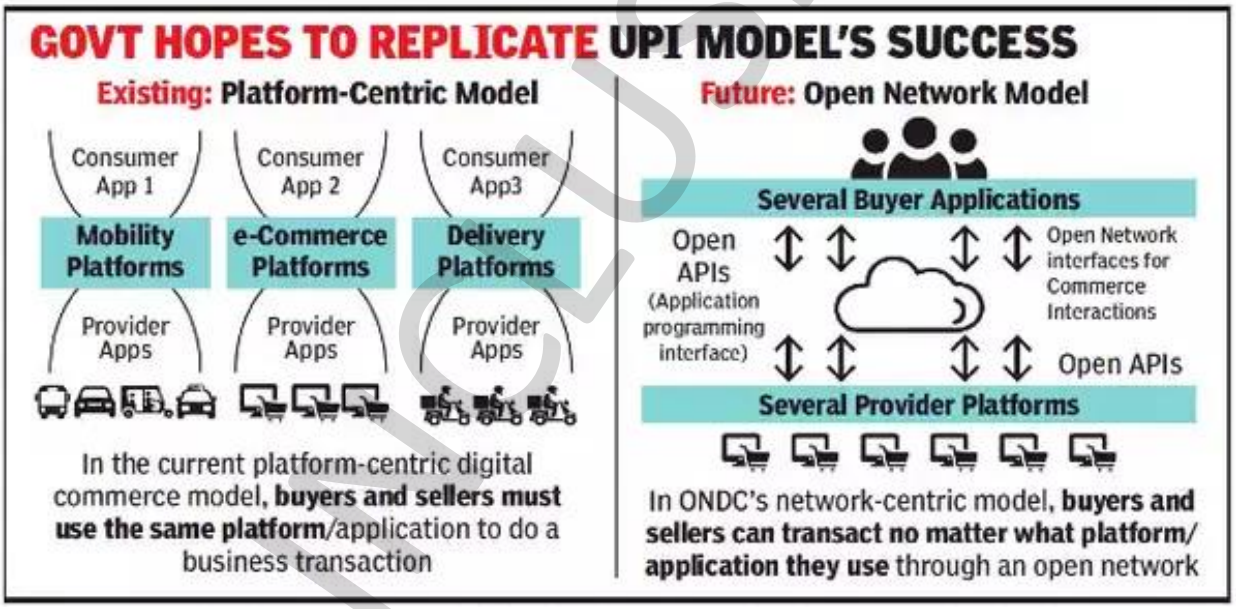

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)

- ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए एक खुला नेटवर्क है
  - जैसे इंटरनेट के लिए http और भुगतान के लिए UPI है, उसी तरह ये भी ओपन प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है।
- यह खरीदार और विक्रेता को ई-कॉमर्स लेन-देन करने के लिए अपनी पसंद के एप्लिकेशन का उपयोग करने देगा
  - वर्तमान में, खरीदार और विक्रेता लेनदेन करने के लिए एक ही (same) एप्लिकेशन (अमेज़ॅन/फ्लिपकार्ट) का उपयोग करते हैं।
- यह कुछ कार्यों का मानकीकरण करेगा
  - सूचीकरण, सूची प्रबंधन, आदेश प्रबंधन, आदेश पूर्ति
- खरीदारों को अधिक विकल्प देगा
  - खरीदार एक ही वस्तु के लिए कई विक्रेता खोज पाएंगे
- स्थानीय विक्रेताओं को बढ़ावा देगा
  - जो अमेज़न/फ्लिपकार्ट पर नहीं हैं, वे भी ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे

औषधकोश *Pharmacopoeia*

THE HINDU

Strive for global recognition for Indian Pharmacopoeia: Health Minister

India has become 'pharmacy of the world' by specialising in generic medicine formulation, says Mansukh Mandaviya

July 01, 2022 07:49 pm | Updated 07:49 pm IST - NEW DELHI

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC)

- 2009; MoH&FW के अंतर्गत
- MoH&FW के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं
- यह इंडियन फार्माकोपिया (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत) के प्रकाशन द्वारा भारत में मानव तथा पशुओं के लिए दवाओं के प्रमाणिक मानकों का निर्धारण और अपडेट करता है।
- यह नेशनल फॉर्म्यूलरी ऑफ इंडिया (डॉक्टरों और नर्सों के लिए गाइड) के प्रकाशन द्वारा जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।

इंडियन फार्माकोपिया के 2018 संस्करण में संशोधन किया गया

- असामान्य विषाक्तता परीक्षण (गिनी सूअरों और चूहों पर प्रयोग कर देखा जाता है कि क्या कोई मृत्यु हुई)
- पाइरोजेन टेस्ट (खरगोशों पर किया जाता है बुखार देखने के लिए)

उपरोक्त परीक्षणों को टेस्ट ट्यूब परीक्षणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

बल्क ड्रग पार्क *Bulk Drug Park*

THE HINDU

Gujarat, A.P. and Himachal to have bulk drug parks

Health Minister Mansukh Mandaviya said that the new parks would help supply raw material for pharmaceutical industries

December 16, 2022 09:25 pm | Updated December 17, 2022 01:49 am IST - NEW DELHI

सक्रिय दवा सामग्री (API) (*बल्क ड्रग्स*)

- ये दवा का जैविक रूप से सक्रिय घटक हैं
- ये दवा को उपचारात्मक प्रभाव देते हैं
- भारत दवाइयों का 68% API चीन से आयात करता है

जैविक रूप से सक्रिय का मतलब यह नहीं है कि इनमे सूक्ष्म जीवाणु हैं। इसका मतलब यह है कि वे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

फार्मा विभाग किसके अंतर्गत आता है ?

✓ रसायन और उर्वरक मंत्रालय

X स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

जन औषधि , दवा मूल्य नियंत्रण, दवाओं/चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना, फार्मा PSU आदि।

API **Excipient**

मेडिसिन = API + एक्सीपिएंट (सहायक)

API शरीर का इलाज करता है

एक्सीपिएंट बाइंडर की तरह होता है

एक्सीपिएंट की आवश्यकता क्यों होती है?

रूहअफ़ज़ा: सीरप API है, पानी एक्सीपिएंट है

नींबू पानी: नींबू API है, पानी एक्सीपिएंट है

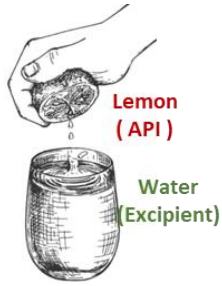

NPPA

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority)

- स्थापना 1997 में; औषध (फार्मास्यूटिकल्स) विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के अंतर्गत
- औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) 2013 लागू करना (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी)
- दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना , कमी की पहचान करना और उपचारात्मक कदम उठाना
- क्या यह भारत में सभी दवाओं की कीमत तय करता है? नहीं
  - स्वास्थ्य मंत्रालय आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) बनाता है
  - NLEM के तहत दवाएं स्वतः रूप से DPCO 2013 के तहत आ जाती हैं
  - NPPA इन दवाओं की उपलब्धता और कीमत लागू करता है

जन औषधि

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

2008 : 'जन औषधि योजना' (JAS) शुरू की

2015 : नया नाम 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' (PM-JAY)

2016 : नया नाम 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' (PM-BJP)

ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू (PSUs) ऑफ इंडिया

- 2008 में स्थापित
- औषध (फार्मास्यूटिकल्स) विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) के अंतर्गत
- जन औषधि स्टोर्स के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना
- नया नाम: फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड
यह दूरसंचार विभाग के तहत एक निकाय (या कोष) है

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए

Ministry of Communications

Universal Service Obligation Fund (USOF) launches Telecom Technology Development Fund scheme

Posted On: 01 OCT 2022 5:03PM by PIB Delhi

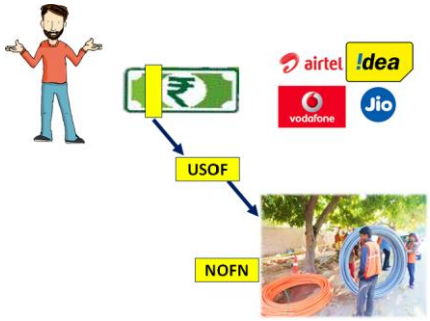

नई दूरसंचार नीति 1999

- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के लिए पैसा 'यूनिवर्सल एक्सेस लेवी' (UAL) से आएगा
- UAL विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटर्स द्वारा अर्जित राजस्व का कुछ प्रतिशत होगा (जैसे समायोजित सकल राजस्व Adjusted Gross Revenue)

डार्क फाइबर

- अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर
- इसे अन्य दूरसंचार प्रदाताओं को लीज पर दिया जा सकता है
- प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां BBNL के डार्क फाइबर का इस्तेमाल कर रही हैं

NOFN ←	2011	2021
BBNL ←	2012	2022
	2013	2023
	2014	2024
BharatNet ←	2015	2025
	2016	
	2017	
	2018	
NBM ←	2019	
	2020	

Background (Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)

- **2011** : USOF का उपयोग करके सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए NOFN शुरू किया गया
- **2012** : NOFN बनाने और संचालित करने के लिए BBNL (संचार मंत्रालय के तहत) की स्थापना की गई
- **2015** : NOFN का नाम बदलकर भारतनेट कर दिया गया
- **2019** : NBM ने घोषणा की कि NOFN 2022 तक पूरा हो जाएगा
- **2022** : समय सीमा 2025 तक बढ़ाई गई

NOFN : राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
BBNL : भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
NBM : राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

गतिशक्ति संचार पोर्टल

- केंद्रीकृत **राइट ऑफ वे** (RoW) अनुमोदन के लिए
- **दूरसंचार विभाग** (संचार मंत्रालय) की पहल
- मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित

https://sugamsanchar.gov.in/

Ministry of Communications

Department of Telecommunication Launches "GatiShakti Sanchar" Portal for Centralised Right of Way (RoW) approvals

Newly Launched "GatiShakti Sanchar" Portal will Streamline the process of Right of Way (RoW) Applications and permissions Across the Country

Posted On: 14 MAY 2022 2:17PM by PIB Delhi

Background (Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)

- टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लगाने और मोबाइल टावर लगाने के लिए राज्य/स्थानीय निकायों से अनुमति की आवश्यकता होती है
- मुद्दे: अनुमति से इनकार, मंजूरी में देरी, राज्यों में गैर-समान प्रक्रिया, केंद्र-राज्य समन्वय
- GatiShakti Sanchar Portal इन कंपनियों के लिए RoW एप्लिकेशन फाइल करने के लिए बनाई गई एक वेबसाइट है
- चूंकि सरकार के सभी स्तर (केंद्र/राज्य/स्थानीय) पोर्टल पर मौजूद हैं, इसलिए इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी

BusinessLine

Govt launches e-commerce marketplace for driving exports

May 27, 2022 - Updated 09:19 pm IST

Indian Business Portal, an online global trade hub for exporters and foreign buyers, was launched on Friday to empower MSMEs to identify new markets, according to a statement issued by exporters' body FIEO.

इंडिया बिजनेस पोर्टल

भारतीय *बिजनेस* पोर्टल

- विशेष रूप से भारत में पंजीकृत निर्यातकों के लिए B2B मार्केटप्लेस
- इससे SMEs, सेवा प्रदाताओं, GI Tag प्रोडक्ट्स आदि को लाभ होगा।
- इसे FIEO द्वारा विकसित किया गया है

भारतीय निर्यात संगठनों का संघ (FIEO)

- 1965 में वाणिज्य मंत्रालय और निजी उद्योगों द्वारा स्थापित।
- यह सरकार के साथ मिलकर निर्यात को बढ़ावा देता है
- यह भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और विकास प्राधिकरणों का शीर्ष निकाय है।

Ministry of Commerce & Industry

Foreign Investment Facilitation Portal (FIF) completes 5 years since Union Cabinet decision to abolish FIPB

Posted On: 24 MAY 2022 2:48PM by PIB Delhi

भारत में FDI

2014-15 : $45 बिलियन
2021-22 : $83 बिलियन
i.e. पिछले 7 वर्षों में भारत में औसतन FDI सालाना 10% बढ़ा है

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल

Foreign Investment Facilitation Portal

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB)

- FDI प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए LPG सुधारों (1991) के बाद बना
- 2017 में FIFP द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP)

- अनुमोदन मार्ग (Approval Route) द्वारा FDI प्रस्तावों पर कार्यवाही करना
- DPIIT (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा प्रबंधित
- DPIIT आवेदन को मंजूरी के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजता है
- RBI, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से भी टिप्पणियां मांगी जाती हैं

DPIIT उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

NIPUN

Ministry of Housing & Urban Affairs

Shri Hardeep S. Puri launches National Initiative for Promotion of Upskilling of Nirman workers (NIPUN)

Posted On: 20 JUN 2022 4:27PM by PIB Delhi

निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल
(National Initiative for Promotion of Upskilling of Nirman workers)

- मंत्रालय : MoHUA
- क्रियान्वन : राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (MSDE)
- निर्माण श्रमिकों को मिलेगा
  - DAY-NULM के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण
  - कौशल विकास योजना के माध्यम से 3 साल के लिए 2 लाख रुपये का 'कौशल बीमा' (दुर्घटना बीमा)

DAY-NULM

- 2013 में MoHUA द्वारा लॉन्च किया गया
- केंद्र प्रायोजित योजना
- स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी परिवारों में गरीबी कम करना।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

लाइट हाउस प्रोजेक्ट

- 2019 में MoHUA द्वारा लॉन्च किया गया
- मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट (लगभग 1,000 घरों के साथ)
- प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तेजी से मकान बनाने के लिए (क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप)

ALL INCLUSIVE IAS

संशोधन (Correction) Class-16 pg-87

इसे भूल जाएं (क्लास-16 पेज-87)	इसे याद रखें
क्या शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है? ❑ USA में हाँ भारत में नहीं ❑ हालांकि व्यावहारिक रूप से आप भारत में भी इंट्रा-डे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं।	भारत में शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है USA में शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है USA में नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं है

शॉर्ट सेलिंग (Copied from: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/ssframe_p.pdf)

- "शॉर्ट सेलिंग" की परिभाषा - एक ऐसे स्टॉक को बेचना **जो ट्रेड के समय विक्रेता के पास नहीं है**
- **सभी प्रकार के निवेशकों** (जैसे खुदरा और संस्थागत निवेशक) को शॉर्ट सेल करने की अनुमति होगी
- **F&O सेगमेंट** में ट्रेड होने वाली प्रतिभूतियां (securities) शॉर्ट सेलिंग के लिए पात्र होंगी
- भारतीय प्रतिभूति बाजार में **नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं** है और इसीलिए, सभी निवेशक सेटलमेंट के दौरान प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए बाध्य होंगे ।
- शॉर्ट सेल को प्रोत्साहन देने के लिए सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) हेतु एक योजना बनाई जाएगी।

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (Copied from: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/slbframe_p.pdf)

- SEBI द्वारा सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम (SLS), 1997 प्रकाशित की गई थी
- **सभी प्रकार के निवेशकों** (जैसे खुदरा, संस्थागत आदि) को प्रतिभूतियां उधार लेने और उधार देने की अनुमति होगी।
- इस स्कीम के तहत, **F&O सेगमेंट** में ट्रेड होने वाली प्रतिभूतियां उधार ली और उधार दी जा सकेगी
- SLB को स्टॉक एक्सचेंजों के Clearing Corporation/Clearing House के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो SLS,1997 के तहत Approved Intermediaries (AIs) के रूप में पंजीकृत होंगे।

THE WIRE SUPPORT

Explainer: Everything You Need to Know About Short Selling, and How it is Done in India

At present, in a realistic sense, there is no short selling in India. It's done in the form of day trading, futures trading, etc. But actual short selling – which involves borrowing shares for a multi-day horizon – is absent in India.

https://zerodha.com/varsity/chapter/shorting/

Shorting in the spot market has one restriction – it strictly has to be done on an intraday basis. Meaning you can initiate the short trade anytime during the day, but you will have to buy back the shares (square off) by end of the day before the market closes. You cannot carry forward the short position for multiple days.

Shorting a stock in the futures segment has no restrictions like shorting the stock in the spot market. In fact this is one of the main reasons why trading in futures is so popular. Remember the 'futures' is a derivative instrument

यह व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है क्योंकि

1. SLB सिस्टम जटिल व धीमा है और इसमें कम तरलता (बाजार सहभागियों की संख्या कम) है
2. शॉर्ट सेलिंग का उद्देश्य डेरिवेटिव मार्केट (जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) के माध्यम से आसानी से हासिल किया जाता है

ALL INCLUSIVE IAS